International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 28-09-2021, Accepted: 14-10-2021, Published: 29-10-2021
Volume 7, Issue 5, 2021, Page No. 110-111

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभाव से विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का अध्ययन

प्रवीण कुमार शुक्ला[1], डॉ. पतंजलि मिश्रा[2]
[1] उच्च माध्यमिक शिक्षक, शा.उ.मा.वि. निपरिया, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
[2] प्राचार्य, श्याम आदर्श शिक्षा महाविद्यालय, पुरैना, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभाव से विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का अध्ययन शोधार्थी द्वारा विद्यालयों के 45 संस्था प्रमुखों से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा आकड़ों का संग्रहण एवं साख्यिकीय विश्लेषण करते हुए किया गया है। अध्ययन रीवा जिले पर किया गया है। सभी जिलों के लिए सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि वास्तविक रूप से मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति बढ़ी है।

मूल शब्दः मध्यप्रदेश के रीवा जिल, मध्यान्ह भोजन योजना, विद्यालयों में विद्यार्थियों

प्रस्तावना
मध्य प्रदेश सहित समूचे देश में विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है, उसी कड़ी में रीवा जिला भी इस योजना से अछूता नहीं है। शोधार्थि की यह जिज्ञासा कि मध्यान भोजन योजना के कारण क्या विद्यालयों में विद्यार्थियों कि दैनिक उपस्थिति पर भी कुछ प्रभाव पडता है। अपने इस प्रश्न की पुष्टी हेतु तथा अपनी जिज्ञासा को शान्त करने हेतु शोधार्थी द्वारा यह अनुसंधान किया गया है। अनुसधान के उद्देश्य अग्रानुसार प्रस्तुत है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से विद्यालयों की शैक्षणिक प्रगति हुई हैं। विद्यालयों में कार्यक्रम के प्रभाव से विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है तथा विद्याालयों में दैनिक उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बच्चों में सीखने के प्रति एकाग्रता में वृद्धि होना स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हे भूखे नही रहना पडेगा उनके भोजन का इंतजाम है भोजन के आभाव में गरीब बच्चों में आग्रता भंग होती है खाली पेट पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रीत नही हो पाता है ग्रहण करने के पहले बच्चों द्वारा भोजन मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अतः उनमें एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण होता है मध्यान्ह भोजन के अभाव में बच्चे कुपोषित हो जाने से बच जाते है इस योजना के प्रभाव से ज्यादा फीसदी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय आते है तथा ज्यादा फीसदी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुच जाते है। इस तरह कहा जा सकता है कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभाव से बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ हैं

शोध के उद्देष्य
रीवा जिले में मध्यान भोजन योजना का विद्यालयों में विद्यार्थियों कि उपस्थिति के प्रभाव का अध्यन।

परिकल्पना
मध्यान्ह भोजन योजना लागू होने के बाद शासकीय शालाओं में दैनिक उपस्थित बढ़ी है।

उपकरण
साक्षात्कार अनुसूची।

न्यादर्ष
रीवा जिले के 45 प्रधानाध्यापक

परिसीमन
मध्य प्रदेश के रीवा जिले के 9 विकासखण्ड।

तालिका 1: मध्यान्ह भोजन का विद्यालयों में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन

कथन	प्रधानाध्यापकों के मत			
मध्यान्ह भोजन योजना के कारण दैनिक उपस्थिति बढ़ी है।	पक्ष में	विपक्ष में	अनिश्चित	योग
	37	08	00	45

स्वतंत्रता की कोटि 02 पर सार्थकता के लिए आवश्यक काई–वर्ग का मान 5 प्रतिशत विश्वास स्तर पर 5.99 तथा 01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर 9.21 है तथा उपर्युक्त आकड़ों से प्राप्त काई–वर्ग का मान 50.54 है, जो काई–वर्ग के उक्त दोनों स्तर (5 एवं 01 प्रतिशत) के मानों क्रमशः 5.99 तथा 9.21 से अधिक है। अतः यहॉ पर शून्य परिकल्पना का कोई अस्तित्व नही है। कथन के पक्ष में सर्वाधिक आकड़े हैं (कुल 37) अतः शोधार्थी की परिकल्पना क्रमांक–4 ''मध्यान्ह भोजन योजना लागू होने के बाद शासकीय शालाओं में दैनिक उपस्थिति बढ़ी है।'' स्वीकृत हेती है।

परिणाम एवं निष्कर्ष
मध्यान्ह भोजन योजना के कारण शासकीय विद्यालयों में दैनिक उपस्थिति बढ़ी है। मध्यान्ह भोजन योजना के कारण बच्चे विद्यालय में ज्यादा उपस्थित हो रहे है। जिस दिन मध्यान्ह भोजन नही बनता हैं इस बात की सूचना यदि बच्चे पूर्व में पा जाते हैं तो उस सम्बधित दिन को विद्यालय नही आते है ऐसा अध्ययन में परिलक्षित हुआ है।

संदर्भ
1. कपिल, एच.के. (1985) ''अनुसंधान विधिया'' अगरा भार्गव प्रकाशन

2. शर्मा, आर.ए. (1992) ''शिक्षा तकनीकी'' मेरठ, लायल बुक डिपो
3. कपिल, एच.के. (1998) ''सांख्यिकी के मूल तत्व'' आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर
4. मध्यान्ह भोजन योजना (2004) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।